IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 8, Issue 7, July 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 7, July 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0807024|

इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी- एक ऐतिहासिक अध्ययन

Dr. Abhinandan Swaroop

M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh, India

सार

बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी (IIC) के इतिहास को उपमहाद्वीप के बाहर दक्षिण एशियाई लोगों के उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के साथ-साथ रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों को अस्थिर करने के उद्देश्य से बड़े जर्मन "क्रांति के कार्यक्रम" के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। " [1] यह रणनीति काफी हद तक मैक्स फ्रीहेर वॉन ओपेनहेम के (1860-1946) "हमारे दुश्मनों के इस्लामी क्षेत्रों में क्रांति लाने पर ज्ञापन" (1914) पर आधारित थी। भारत , ग्रेट ब्रिटेन के सबसे बड़े उपनिवेश के रूप में, साम्राज्य की दुखती रग माना जाता था और इसलिए इस ज्ञापन में एक रणनीतिक भूमिका निभाई। जर्मन अधिकारियों ने यह मान लिया था कि भारत और जर्मनी में जल्द ही उपनिवेशवाद विरोधी विद्रोहों की उम्मीद की जा सकती हैइन विकासों का समर्थन करने का प्रयास किया।

इस रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, 1914 में विदेश कार्यालय के भीतर पूर्व के लिए एक विशेष सूचना सेवा (नाक्रिचटेनस्टेल फर डेन ओरिएंट , एनएफओ) की स्थापना की गई थी। एनएफओ के समर्थन से, आईआईसी ने अमेरिका में ग़दर पार्टी के साथ मध्यस्थता की थी और समिति के सदस्यों की भर्ती के लिए लंदन, बर्न, जिनेवा और ज्यूरिख में भारतीय क्रांतिकारियों के मौजूदा यूरोपीय नेटवर्क के लिए । बर्लिन समिति से जुड़े प्रसिद्ध भारतीय थे: वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय (1880-1937) , अभिनाश चंद्र भट्टाचार्य (1882-1962) , ताराचंद रॉय (1890-1952) , मंसूर अहमद (1898-1979) , मौलवी बरकातुल्लाह (1854-1927) ।तारकनाथ दास (1884-1958) , बीरेंद्रनाथ दासगुप्ता, भूपेंद्र नाथ दत्ता (1880-1961) , और भाई अब्देल जब्बार खीरी (1880-1958?) और अब्देल सत्तार खीरी (1885-1953)

परिचय

बर्लिन भारतीय स्वतंत्रता समिति के मुख्य कार्यों में शामिल हैं: फारस की खाड़ी के लिए एक मिशन तैयार करना "ताकि वहां भारतीय सैनिकों को तुर्की और फारसी सेनाओं से न लड़ने के लिए राजी किया जा सके"; अफ़ग़ानिस्तान के अमीर के लिए एक मिशन आयोजित करने के लिए अफ़ग़ान क्षेत्र से एक भारतीय बटालियन के साथ भारत में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए और जर्मनी में युद्ध के दक्षिण एशियाई कैदियों के बीच प्रचार करने के लिए, सबसे पहले वुन्सडॉर्फ में तथाकथित हलबमंडलागर में . [2] इस प्रकार, IIC के सदस्य 1915 में वर्नर ओटो वॉन हेंटिग (1886-1984) के नेतृत्व में प्रसिद्ध अफगानिस्तान मिशन में शामिल थे ।[1] अन्य लोगों ने शिविर अखबार हिंदोस्तान के उत्पादन में भाग लिया।(हिंदी और उर्दू में) जर्मनी में युद्ध के दक्षिण एशियाई कैदियों के लिए।युद्ध के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि भारत में क्रांति लाने की योजना के साथ-साथ जर्मन जिहाद -प्रचार विफल हो गया। आईआईसी के भीतर, पैन-इस्लामवाद के प्रति दृष्टिकोण, भारत में वास्तविक स्थिति के विरोधाभासी आकलन और अलग-अलग राजनीतिक लक्ष्यों सहित धार्मिक मतभेद आंतरिक घर्षण का कारण बने।[2] 1917 में, व्यक्तिगत समिति के सदस्यों ने स्विट्जरलैंड , नीदरलैंड और स्वीडन जैसे तटस्थ देशों में नई शाखाएँ खोलीं । युद्ध के अंत में, बर्लिन अब "विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों" के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नहीं था [3] और बर्लिन भारतीय स्वतंत्रता समिति के विघटन की आधिकारिक घोषणा की गई। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयो को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिये प्रेरित करना था। इसकी स्थापना भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने १९२८ में की थी। यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया एवं मुख्य भूमि से अलग भारतीय क्षेत्रों में आधारित रहा।[3] भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा 1928 में स्थापित यह संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित थे, [27] इसमें कई भारतीय प्रवासी शामिल थे और बाद में निर्वासन झेल रहे भारतीय राष्ट्रवादी, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भाग के दौरान जापान के सफल मलायन अभियान के बाद इसमें शामिल हो गये।[4] मलाया में जापानी शासन के दौरान, जापानियों ने मलाया में रह रहें भारतीयों को भारतीय स्वतंत्रता लीग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।[1]

मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जापानी समर्थन प्राप्त करने के लिए स्थापित लीग के तहत मोहन सिंह के नेतृत्व में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, हालांकि बाद में इसे भंग कर दिया गया। [26] बाद में, दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के बाद, उन्होंने इसी ढ़ाचे का उपयोग कर आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी। दक्षिण-पूर्व एशिया में जापानी कब्जे के साथ, एक बड़ी प्रवासी भारतीय आबादी भी इसमें शामिल था।[5] युद्ध के

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 7, July 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0807024|

मलाया पहुंचने से पहले ही वहाँ स्थानीय भारतीय संघों का ढांचा अस्तित्व में था। इनमें से सबसे बड़ी प्री-वॉर सेंट्रल इंडियन एसोसिएशन, सिंगापुर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और अन्य संगठनों थे, और उनके सदस्यों में प्रमुख भारतीय प्रवासी, उदाहरण के लिए के. पी. केशव मेनन,[25] नडियाम राघवन, प्रीतम सिंह, एससी गोहो और अन्य आदि थे। व्यवसाय प्राधिकरण के प्रोत्साहन के साथ, इन समूहों ने स्थानीय भारतीय स्वतंत्रता लीग में मिलना शुरू कर दिया और स्थानीय भारतीय आबादी और जापानी कब्जे के बल के बीच प्रमुख उभरते संगठन बन गए। सभी सदस्यो को एक आईआईएल कार्ड बाटा गया।[6] जिसे दिखाये जाने पर रेलवे टिकट की खरीदी में आसानी आई और आईआईएल मुख्यालयों में इन कार्ड का प्रयोग कर उचित कीमतों पर मुश्किल से मिलने वाले सामानों जैसे टुथ-पेस्ट और साबुन की खरीदारी की आसानी से की जा सकती थी।[2] इसके माध्यम से राशन भी जारी किए जाते थे।[3] इसके अलावा, चूंकि आईआईएल को स्विस रेड क्रॉस के साथ काम करने की इजाजत थी, इसलिए सदस्यों को सिलोन जैसे कठिन स्थानों के लिए पत्र भेजना और पाना आसान हो गया था।[2]

विचार-विमर्श

रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1912 के दिल्ली-लाहौर षडयंत्र की योजना -जिसमें तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की शाजिश थी- में और 1915 के गदर षड्यंत्र में भागीदारी निभाई थी। ब्रिटीश राज द्वारा खोजने के अथक प्रयाश के बीच, रासबिहारी जापान चले गए, जहां उन्हें जापानी देशभक्ति समाजों के बीच शरण मिला।[7] बाद में रासबिहारी ने जापानी भाषा सीखी, और एक जापानी महिला से विवाह कर स्वाभाविक जापानी नागरिक बन गये।[4] मलयान अभियान से पहले और उसके दौरान, रासबिहारी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य से जापानीयों में रुचि बढाने की कोशिश की थी।[8] फुजीवाड़ा से रिपोर्ट को प्रोत्साहित कर और स्थानीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना के साथ, आईजीएचक्यू ने भारतीय आंदोलन को आकार देने और विस्तार करने के लिए रासबिहारी से मदद मांगी।रासबिहारी ने आईजीएचक्यू को विकसित राजनीतिक संगठन में आईएनए को विकसित कर संलग्न करने की सलाह दी,[24] जो दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय नागरिक आबादी के लिए भी बात करेगी।[5] मार्च 1942 में, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग के स्थानीय नेताओं को टोक्यो में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया। यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया और प्रतिनिधिमंडल मार्च 1942 के अंत में टोक्यो होटल में मिले थे।हालांकि, टोक्यो सम्मेलन किसी भी निश्चित निर्णय तक पहुंचने में असफल रहा। रासबिहारी को लेकर कई भारतीय प्रतिनिधिमंडल में मतभेद थे,[9] विशेषकर जापान के साथ अपने लंबे संबंध और दक्षिण-पूर्व एशिया में कब्जे वाली शक्ति के रूप में जापान की वर्तमान स्थिति और को देखते हुए, और जापानीयों के बढ़ते दिलचस्पी से सावधान थे।[5] सदस्य गण भविष्य में बैंकाक सम्मेलन में फिर से मिलने के लिए सहमत हो गये।[5] भारतीय प्रतिनिधिमंडल अप्रैल में रासबिहारी के साथ सिंगापुर लौट आया। सिंगापुर में, एक सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता के लिये रासबिहारी को आमंत्रित किया गया था, जिसमें अखिल मलय-भारतीय स्वतंत्रता लीग की घोषणा की गई थी।[5] लीग की अध्यक्षता एक प्रमुख मलय-भारतीय और पेनांग बैरिस्टर, नडियाम राघवन को दी गई थी। शासी बोर्ड में के पी केशव मेनन और एससी गोहो, बाद में सिंगापुर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष शामिल थे।[23] लीग ने कई प्रस्ताव दिए,[10] जिसमें कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य परिषद की रचना, एक ऐसे निकाय का गठन जिसे क्षेत्रीय लीग रिपोर्ट कर सके, साथ ही साथ आईएनए और परिषद के बीच एवं परिषद और जापानी अधिकार के बीच संबंध स्थापित करना आदि शामिल थे।[5] इन प्रस्तावों पर, टोक्यो सम्मेलन में मिले प्रतिनिधित्व की तुलना में ज्यादा लोगो से मत कराने और अगली बैठक जापानी जमीन से दूर कराने के लिये मतदान करने के लिए निर्णय लिया गया था। लीग के शिविरों के निर्देशक निर्जन सिंह गिल समेत लीग के कई सदस्य, लीग और स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में जापानी इरादों से डरते थे।[6] लीग को भारतीय आबादी के बीच व्यापक समर्थन मिला; अगस्त के अंत तक सदस्यता एक सौ से हजार के करीब पहुचंने का अनुमान लगाया गया था।[11] लीग के सदस्यों को, युद्ध के मध्य में आपातकाल के दौरान और आधिपत्य अधिकारियों से निपटने के दौरान, जनसंख्या को लाभ मिला। लीग की सदस्यता कार्ड धारक के द्वारा भारतीय[22] (और इस प्रकार एक सहयोगी) के रूप में पहचान, इसका इस्तेमाल कर राशन जारी करना जैसे कार्य आसान हो गया।[3] इसके अलावा, लीग ने स्थानीय भारतीय आबादी की स्थितियों में सुधार करने के प्रयास किए, जिसमें बेरोज़गार हुए बागान मजदूरों के कारण शामिल थे।[5] जून 1942 में, बैंकाक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग का संविधान रखा गया। [12] लीग में काउंसिल फॉर एक्शन और इसके नीचे प्रतिनिधियों की एक समिति शामिल थी। समिति के नीचे क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएं थीं।[7] रासबिहारी बोस परिषद की अध्यक्ष थे, जबकि के पी केशव मेनन, नडियाम राघवन परिषद के नागरिक सदस्यों में से थे।[21] मोहन सिंह और गिलानी के नाम से एक अधिकारी, आईएनए के सदस्य थे।[7] प्रतिनिधियों की समिति के सदस्य के लिये भारतीय जनसंख्या वाले 12 क्षेत्रों के सदस्यों को चुना गया था, जिसमें प्रतिनिधि भारतीय आबादी के अनुपात में रखे गये थे।[7][8] बैंकाक सम्मेलन में निर्णय लिया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को इसके अधीनस्थ किया जाना चाहिए।[7]

परिणाम

बैंकाक सम्मेलन में एक चौबीस बिंदु संकल्प को अपनाया गया और जापानी सरकार से प्रत्येक बिंदु पर जवाब की उम्मीद लगाई गई।[20] इनमें जापानी सरकार से स्पष्टतया और सार्वजनिक रूप से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र और लीग को देश का प्रतिनिधि और अभिभावक के रूप में पहचान देने की माँग की गई।[7] अन्य बिंदुओं में उनसे आज़ाद हिंद की जापानी संबंध स्पष्ट करने, उनकी संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की मांग की गई,[13] इसके अलावा सभी ने सर्वसम्मति से मांग की कि

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 7, July 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0807024|

जापान स्पष्ट और प्राथमिक रूप से लीग को आगे लाने की प्रतिबद्धता दिखायेगा।[9] संकल्प में आगे मांग की गई कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक सहयोगी सेना की स्थिति दी जाएगी और उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा, और सभी भारतीय पीओयू को आईएनए के लिये रिहा कर दिया जाएगा। जापानियों को सेना के लिये ऋण की मदद करनी चाहिए, और भारत की मुक्ति के मुकाबले के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये मार्च करने को नहीं कहा जाना चाहिए।[7] संकल्प को जापानी अधिकारी इवाकुरो किकन सौंप दिया गया।नवंबर 1943 में, ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन टोक्यो में आयोजित किया गया था। राज्य के प्रमुख जो ग्रेटर ईस्ट एशिया सह-समृद्धि क्षेत्र के सदस्य थे, एकत्र हुए थे।[14] सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में भाग लिया था। 1945 में, जकार्ता के भारतीय समुदाय के नेता प्रीतम सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता लीग और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष दोनों में हिस्सा लिया था।[10]

1972 में, केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना[11] शुरूआत की। जिसके माध्यम से स्वतंत्रता कार्यकर्ता पेंशन के हकदार थे।[12] हालांकि, इस योजना को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरोध किया गया था।[12] उदाहरण के लिए, एसएमएम शनमुगम को पेंशन पाने के लिये 24 साल की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, और उन्हें अंतत: अगस्त 2006 में पेंशन प्राप्त हुई।[12]

निष्कर्ष

बर्लिन समिति (1915 के बाद से भारतीय स्वतंत्रता समिति ; जर्मन: दास इंडिस्की अनभांगिग्केट्स्कोमी), 1914 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और देश में रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में गठित एक संगठन था।[19] समिति का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। प्रारंभ में इसे बर्लिन-भारतीय समिति कहा जाता था, संगठन का नाम बदलकर 1915 में भारतीय स्वतंत्रता समिति रखा गया, और हिंदु-जर्मन षडयंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। समिति के प्रसिद्ध सदस्यों में वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय (उर्फ चट्टो),[15] चेम्पाकरमन पिल्लई और अबिनाश भट्टाचार्य शामिल थे।कई भारतीयों, विशेष रूप से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंग्लैंड में इण्डिया हाउस का गठन किया था। यह संगठन, दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा और इन जैसे अन्य भारतीय दिग्गजों के समर्थन के साथ भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति की पेशकश,[18] राष्ट्रवादी कार्य का पदोन्नत, और उपनिवेश विरोधी राय और विचारों के लिए एक प्रमुख मंच था। कृष्णा वर्मा द्वारा प्रकाशित द इंडियन सोसियोलोजिस्ट, एक प्रशिध्द औपनिवेशिक विरोधी पत्रिका थी। इंडिया हाउस से जुड़े प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों में दामोदर सावरकर,[16] वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय (उर्फ चट्टो) और हर दयाल शामिल थे।ब्रिटिश सरकार ने अपने काम की प्रकृति और द इंडियन सोसियोलोजिस्ट के उत्तेजित स्वर के कारण इंडिया हाउस पर नजर रखना चालु कर दिया, जिसमें कई बार ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों की हत्या का करने का सुझाव दिया जाता था। 1909 में, इंडिया हाउस के साथ निकटता से जुड़े मदनलाल ढींगरा ने भारत के विदेश सचिव के राजनीतिक एडीसी विलियम हट कर्ज़न वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद, इंडिया हाउस को तेजी से दबा दिया गया और कृष्ण वर्मा समेत इसके कई प्रमुख नेताओं को यूरोप भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।[17] कुछ, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय सहित, जर्मनी चले गए, जबकि कई नेता पेरिस चले गए।[1]

संदर्भ

1. ↑ जेनकींस, जेनिफर: फ्रिट्ज फिशर का "रेवोल्यूशन के लिए कार्यक्रम": प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के वैश्विक इतिहास के लिए निहितार्थ: जर्नल ऑफ़ कंटेम्परेरी हिस्ट्री 48/2 (2013), पी। 402.
2. ↑ लीबाऊ, हेइके: द जर्मन फॉरेन ऑफिस, इंडियन इमिग्रेंट्स एंड प्रोपेगैंडा एफर्ट्स अमंग द 'सिपॉयज' में: रॉय, फ्रांज़िस्का / लीबाऊ, हेइके / आहूजा, रवि (संपा.): 'जब युद्ध शुरू हुआ तो हमने कई राजाओं के बारे में सुना' प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध के दक्षिण एशियाई कैदी जर्मनी, नई दिल्ली: 2011, पीपी। 96-129, यहां पृष्ठ 105।
3. ↑ बोस, एसी: विदेश में भारतीय क्रांतिकारी: 1905-1927, नई दिल्ली 2002।
4. Sankar, Uthaya. (11 February 2004) New Straits Times. What Tamil writers? Archived 2011-05-16 at the Wayback Machine
5. ↑ Balachandran, PK. (17 April 2006) Hindustan Times. Netaji's army as seen by a Ceylonese recruit. Archived 2018-08-17 at the Wayback Machine Colombo diary.
6. ↑ Fay 1993, पृष्ठ 92
7. ↑ Fay 1993, पृष्ठ 90
8. ↑ Fay 1993, पृष्ठ 91
9. ↑ Fay 1993, पृष्ठ 93
10. ↑ Fay 1993, पृष्ठ 108
11. ↑ Green 1948, पृष्ठ 61

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 7, July 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0807024|

12. ↑ Fay 1993, पृष्ठ 144
13. ↑ Jakarta Post. (3 June 2003) Indian community leader dies. Section: Features; Page 20.
14. ↑ "Swathantra Sainik Samman Pension Scheme" (PDF). मूल से 5 जुलाई 2007 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 17 अगस्त 2018.
15. ↑ The Hindu. (22 August 2006) Centre asked to pay pension to freedom fighter's widow. Archived 2011-07-14 at the Wayback Machine
16. ↑ The Hindu (25 September 1998) Film maker with a mission.
17. ↑ Urquhart, James. (7 August 2000) The Independent Monday Book: A 'Doctor Zhivago' for the Far East - Review of The Glass Palace.
18. Dignan, Don (February 1971), "The Hindu Conspiracy in Anglo-American Relations during World War I", The Pacific Historical Review, University of California Press, 40 (1): 57–76, doi:10.2307/3637829, ISSN 0030-8684, JSTOR 3637829
19. Newsletter of the Regional Office-South East Asia. German Academic Exchange Service.
20. "Champak-Chatto And the Berlin Committee".Bharatiya Vidya Bhavan
21. Hoover, Karl. (1985), "The Hindu Conspiracy in California, 1913–1918. German Studies Review, Vol. 8, No. 2. (May, 1985), pp. 245–261", German Studies Review, German Studies Association, ISSN 0149-7952.
22. Fraser, Thomas G (1977), "Germany and Indian Revolution, 1914–18. Journal of Contemporary History, Vol. 12, No. 2 (Apr., 1977), pp. 255–272.", Journal of Contemporary History, Sage Publications, ISSN 0022-0094.
23. Ansari, K.H. (1986), Pan-Islam and the Making of the Early Indian Muslim Socialist. Modern Asian Studies, Vol. 20, No. 3. (1986), pp. 509–537, Cambridge University Press.
24. Sims-Williams, Ursula (1980), "The Afghan Newspaper Siraj al-Akhbar. Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Vol. 7, No. 2. (1980), pp. 118–122", Bulletin, London, Taylor & Francis Ltd., ISSN 0305-6139.
25. Hughes, Thomas L (2002), "The German Mission to Afghanistan, 1915–1916.German Studies Review, Vol. 25, No. 3. (Oct., 2002), pp. 447–476.", German Studies Review, German Studies Association, ISSN 0149-7952.
26. Seidt, Hans-Ulrich (2001), "From Palestine to the Caucasus-Oskar Niedermayer and Germany's Middle Eastern Strategy in 1918.German Studies Review, Vol. 24, No. 1. (Feb., 2001), pp. 1-18", German Studies Review, German Studies Association, doi:10.2307/1433153, ISSN 0149-7952, JSTOR 1433153.
27. Liebau, Heike (2019): ""Unternehmungen und Aufwiegelungen": Das Berliner Indische Unabhängigkeitskomitee in den Akten des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts (1914–1920)." In: MIDA Archival Reflexicon, ISSN 2628-5029, 1–11.

Impact Factor: 7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com